

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2302

06 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: एनएफएसएम के अंतर्गत पोषक अनाज हेतु सहायता

2302. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा के अवसर के रूप में 'गोल्डन ग्रेन' मिलेट्स (श्रीअन्न) को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करने, उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और मूल्य शृंखला को सुदृढ़ बनाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार सावर्जनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पोषक अनाज/श्रीअन्न को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)-पोषक अनाजों (श्रीअन्न) (एनआईएसएम) के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को पैदावार वाली किस्मों/संकर बीजों के वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरणों, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरणों आदि जैसे हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान की जाती है; और
- (घ) वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान एनएफएसएम-पोषक अनाजों के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार ने, भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (आईवाईएम) 2023 के लक्ष्यों को प्राप्त करने और भारतीय मिलेट्स को विश्व-स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय बहु-हितधारक सहभागिता दृष्टिकोण (विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, किसानों, स्टार्ट-अप्स, निर्यातकों, खुदरा व्यापारियों, होटलों, भारतीय दूतावासों आदि को शामिल करते हुए) अपनाया है। आईवाईएम 2023 के दौरान, उत्पादन और उत्पादकता, खपत, निर्यात बढ़ाने, मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने, ब्रांडिंग, स्वास्थ्य लाभों के लिए जागरूकता पैदा करने, आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष को जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न आयोजन किए हैं जिससे भारतीय श्रीअन्न (मिलेट्स), व्यंजनों, मूल्य वर्धित उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। भारत में जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, श्रीअन्न (मिलेट्स) पाककला कार्निवल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम, शेफ सम्मेलन, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की प्रदर्शनी, रोड-शो, किसान मेले, अर्धसैनिक बलों के लिए शेफ प्रशिक्षण, इंडोनेशिया और दिल्ली में आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव आदि के द्वारा श्रीअन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा दिया गया। वैश्विक मिलेट्स (श्रीअन्न) सम्मेलन 18 मार्च से 19 मार्च 2023 तक आईएआरआई, पूसा परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया था। भारत को 'श्रीअन्न' के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की दृष्टि से, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (आईआईएमआर), हैदराबाद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया गया।

आईआईएमआर, हैदराबाद, किसानों, महिला किसानों, गृहिणियों, छात्रों और युवा उद्यमियों को मूल्यवर्धित श्रीअन्न (मिलेट्स) खाद्य उत्पादों, दैनिक व्यंजनों आदि के निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और उन्हें स्व-उद्यम स्थापित करने में सहायता देता है। इस संस्थान ने श्रीअन्न (मिलेट्स) खाद्य पदार्थों के लिए "रेडी टु ईट" और "रेडी टु कुक" तथा "ईटराइट" टैग के तहत श्रीअन्न (मिलेट्स) खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग जैसी मूल्यवर्धित प्रौद्योगिकियां भी विकसित की हैं तथा जागरूकता कार्यक्रम, कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेटर, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर आदि का आयोजन भी किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मिलेट प्रोडक्शन लिंकड इन्सेन्टिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट-बेस्ड प्रॉडक्ट्स (पीएलआईएसएमबीपी) को मंजूरी दी है।

राजस्थान के बाड़मेर के निकट गुड़ामालानी में बाजरा के लिए एक नए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का दिनांक 27 सितंबर 2023 को उद्घाटन किया गया। विश्व-स्तर पर श्रीअन्न अनुसंधान सहयोग और सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करने के लिए "मिलेट्स एंड अदर ऐन्सियेंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव (महर्षि) को जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान अपनाया गया।

श्रीअन्न (मिलेट्स) के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामतः जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत पोषक अनाज (मिलेट) पर एक उप-मिशन क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्यों को उनकी विशिष्ट

आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए ढील भी प्रदान करती है। कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से श्रीअन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा दे सकते हैं।

वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के दौरान, देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी में खेती के लिए सेंट्रल वेराइटी रिलीज कमिटी (सीवीआरसी) द्वारा 253 श्रीअन्न की कुल किस्में जारी की गई हैं, जिनमें ज्वार की 75, बाजरा की 76; कुटकी की 19; चेना की 7; कोदो की 13; रागी की 43; कंगनी की 12, ब्राउन टॉप मिलेट की 1 और सावां की 7 किस्में शामिल हैं।

(ख): मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सेंट्रल पूल के तहत एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर भारत सरकार की पूर्व-स्वीकृति से, एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) के साथ परामर्श करके किसानों से ज्वार, बाजरा, रागी और छह छोटे श्रीअन्न (मिलेट्स) खरीदने की अनुमति प्रदान की गई। इन श्रीअन्न (मिलेट्स) की पूरी मात्रा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली)/ओडब्ल्यूएस (अन्य कल्याणकारी योजनाओं) के तहत वितरित की जाएगी।

(ग): एनएफएसएम- पोषक अनाज के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को उन्नत पद्धतियों पर क्लस्टर प्रदर्शन, उच्च उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/हाइब्रिड बीजों का उत्पादन और वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन परिरक्षण मशीनरी/उपकरणों, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरणों, पादप संरक्षण उपायों, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण, आदि जैसे हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के दौरान एनएफएसएम - पोषक अनाज के अंतर्गत किए गए आवंटन निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आवंटन (केन्द्रीय हिस्सा)	183.90	200.31	314.62	397.23
